

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 46/19

GCMS NO 2019/00145

1. गिराज
2. गोविन्द

अपीलकर्ता श्री अश्विनीलाल पुत्रान झबलू जातियान माली निवासीयान गिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

अपीलांत

वनाम

1. रामस्वरूप पुत्र गंगाविशन जाति मीना निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील वामनवास जिला सवाई माधोपुर
2. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(अपील विरुद्ध मु0नं0 11/19 निर्णय दिनांक 3.10.19 न्यायालय उपजिला कलक्टर, मलारना डूंगर)

अभिभाषक अपीला0 श्री श्याम मोहन शर्मा

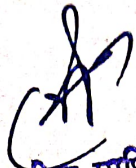
अभिभाषक रेस्पो0 श्री एस0एस0गुप्ता

दिनांक 02.04.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 3.10.19 न्यायालय उपजिला कलक्टर, मलारना डूंगर पेश की है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 रामस्वरूप ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) पेश किया गया था। जिसे जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के आदेश दिनांक 8.7.19 के द्वारा उपखण्ड मलारना डूंगर को स्थानान्तरित की गई। रेस्पो0 संख्या 1 रामस्वरूप द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम महानन्दपुर तहसील गंगापुर सिटी में प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि ख0न0 85 रकबा 0.88 है0 स्थित है। जिस पर प्रार्थी काविज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त भूमि के लगवा एवं पास में ही विपक्षीगण की कृषि भूमि खसरा न0 345/81 रकबा 0.62 है0 स्थित है एवं अप्रार्थीगण की उक्त भूमि से लगता हुआ आम रास्ता है जो गंगापुर सिटी से दौसा को जाता है। प्रार्थी अप्रार्थी की भूमि खसरा न0 345/81 में होकर अपनी खातेदारी की भूमि ख0न0 85 में निर्विवाद रूप से आता जाता रहा है तथा अपने कृषि यंत्रों को ले जाता रहा है। चूंकि रिकार्ड में रास्ता न होने के कारण प्रार्थी को परेशानी हो रही है इसलिए प्रार्थी ने मौका एवं रिकार्ड में रास्ता हेतु प्रार्थना पत्र पेश कर खसरा न0 345/81 रकबा 0.62 है0 में से 0.04 है0 भूमि 8 मीटर लम्बाई व 80 मीटर चौड़ाई का रास्ता दिया जावे। जिसके बदले में मुआवजा राशि अदा करने को तैयार है। प्रार्थी द्वारा चाहे जाने वाले रास्ते से किसी कच्चे रास्ते परेशानी नहीं


राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

होगी। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि में जाने के लिए एक मात्र रास्ता खसरा न० 345/81 में से ही है। विकल्प में और कोई रास्ता विधि अनुकूल नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर भूमि खसरा न० 345/81 रकबा 0.62 है० में से रकबा 0.04 है० बराबर 8 मीटर चौड़ा व 80 मीटर लम्बा रास्ता प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा न० 85 रकबा 0.88 है० में जाने के लिए रास्ता दर्ज किया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से रेस्प० संख्या 1 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलान्त/अप्रार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।


अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्प० को नोटिस जारी कर तलब किया गया। वहस उभयपक्ष अधिवक्तागणों की अपील पर सुनी गई।

अपीलान्त के अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तहत न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं तथ्यों से परे होने से निरस्त योग्य है। तहत न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी अपीलान्त की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि है। जिसे अपीलान्त ने दिनांक 28.10.96 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। क्रय के उपरान्त अपीलान्त ने लाखों रुपये बय कर उक्त आराजी को 5 फीट उंची पक्की बाउन्ड्री बना रखी है। तथा पिछले 17 साल से सफेदे के पेड़ लगा रखे हैं। इस बाबत तहत न्यायालय ने उधान विभाग से पौधों की कीमत की कोई राशि निर्धारित नहीं की है सिर्फ जमीन की डी एल सी दर निकाली गई है। इस बात पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जो विधि विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है। धारा 251 आर टी एक्ट में प्रावधान है कि अब किसी पक्षकार के पास रास्ता उपलब्ध हो जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो तो न्यायालय को नया रास्ता क्रिये नहीं करना चाहिए। अपीलान्त की भूमि में होकर कभी किसी प्रकार का रास्ता नहीं रहा है ना ही रेस्प० इस खेत में होकर आते जाते रहे हैं। रेस्प० को रास्ता निकलवाने का कोई अधिकार नहीं है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि रेस्प० की भूमि के पश्चिम दिशा में खसरा न० 80,81,86,87,91 में होकर जयपुर गंगापुर सिटी रोड से दक्षिण से उत्तर की ओर रास्ता आ रहा है। यह रास्ता ग्राम पंचायत हिगोटिया व तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा कानूनी कार्यवाही कर निकाला गया है। जिसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। रेस्प० ने भूमि खसरा न० 80,81,86,87,91 के खातेदारों के विरुद्ध उक्त रास्ते को खुलवाने सिविल न्यायालय क,ख गंगापुर सिटी में दावा पेश कर रखा है जो विचाराधीन है। इस प्रकार अपीलान्त की भूमि ख० न० 345/81 के पश्चिम में होकर रास्ता रहा है। सिविल कोर्ट के द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई है उसमें यह दर्ज है कि ख० न० 345/81 के पश्चिम में होकर रास्ता मौजूद है। तो तहत न्यायालय ने नया रास्ता प्रार्थी की खातेदारी जो अपीलान्त की भूमि है में होकर रास्ता दर्ज किया जाने का कोई औचित्य नहीं है तथा कई न्यायिक दृष्टान्तों में स्पष्ट


राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर


उल्लेख है कि यदि कोई प्रकरण सिविल न्यायालय में विचाराधीन हो तो दौराने दावा नया प्रकरण राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर निर्णय नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। रेस्पोंडेंट ने अधिनस्थ न्यायालय में तथ्य प्रमाणित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। तहत न्यायालय ने उपरोक्त समस्त तथ्य जबाब प्रार्थना पत्र में एवं राजस्व रिकार्ड से साबित है कि एक रिलीफ हेतु दो न्यायालयों में प्रकरण चलने योग्य नहीं होने से प्रारंभिक तौर पर ही रेस्पोंडेंट का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। इस विषय पर तहत न्यायालय ने किसी प्रकार का कोई विवेचना या मत अपने निर्णय में पारित नहीं किया है। इस कारण तहत न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। जब रेस्पोंडेंट ने रास्ता खुलवाने हेतु प्रार्थना पत्र तहसीलदार के यहाँ वर्ष 2007 में प्रस्तुत किया है उसमें दिनांक 27.7.12 को तहसीलदार द्वारा 30.10.07 से पूर्व की स्थिति बहाल किये जाने के आदेश पारित किये हैं तथा केंदार द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र जो सिविल न्यायालय में पेश किया है उसमें भी स्पष्ट अंकन किया है कि पश्चिम की ओर से कोई रास्ता हमारे उक्त खेत में आने जाने का नहीं रहा है। जो कि स्वयं उक्त आराजी का खातेदार रहा है इस बात पर भी तहत न्यायालय ने अपना कोई मत पारित नहीं किया है तथा तहत न्यायालय ने जल्दबाजी में अपीलाधीन निर्णय खिलाफ कानून पारित किया है। जो निरस्त योग्य है। इस प्रकार अपीलांत की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय के मुकदमा नं० 11/19 में पारित आदेश दिनांक 3.10.19 को निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोंडेंट के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम महानन्दपुर तहसील गंगापुर सिटी में रेस्पोंडेंट/प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि ख० नं० 85 रकबा 0.88 है० स्थित है। जिस पर रेस्पोंडेंट/प्रार्थी काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। रेस्पोंडेंट/प्रार्थी की उक्त भूमि के लगवा एवं पास में ही अपीलांत की कृषि भूमि खसरा नं० 345/81 रकबा 0.62 है० स्थित है एवं अपीलांत की उक्त भूमि से लगता हुआ आम रास्ता है जो गंगापुर सिटी से दौसा को जाता है। रेस्पोंडेंट अपीलांत की भूमि खसरा नं० 345/81 में होकर अपनी खातेदारी की भूमि ख० नं० 85 में निर्विवाद रूप से आता जाता रहा है तथा अपने कृषि यंत्रों को ले जाता रहा है। चूंकि रिकार्ड में रास्ता न होने के कारण रेस्पोंडेंट/प्रार्थी को परेशानी हो रही है इसलिए रेस्पोंडेंट/प्रार्थी ने मौका एवं रिकार्ड में रास्ता हेतु प्रार्थना पत्र पेश कर खसरा नं० 345/81 रकबा 0.62 है० में से 0.04 है० भूमि 8 मीटर लम्बाई व 80 मीटर चौड़ाई का रास्ता प्रदान किये जाने की प्रार्थना अधिनस्थ न्यायालय में टीनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के तहत ही की गई थी। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार द्वारा प्रेषित रिपोर्ट पर अपीलांत द्वारा ऐतराज किये जाने पर पुनः नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी से मौके की रिपोर्ट तलब की गई। नायब तहसीलदार द्वारा भिजवाई गई मौका रिपोर्ट में नायब तहसीलदार द्वारा रेस्पोंडेंट/प्रार्थी की आराजीयात पर आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने पर ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत रास्ते प्रयोजन आने वाली भूमि का दो गुना डी एल सी राशि अपीलांत को प्रदान किये जाने की शर्त पर रास्ता प्रदान किया गया है। जो विधि के प्रावधानों के तहत


राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

ही किया गया है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर अपील पेश की गई है जो निरस्त फरमाई जावे।

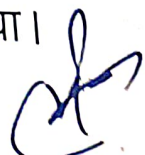
उभयपक्ष अधिवक्तागणों की बहस पर मनन किया गया। अपीलाधीन आदेश एवं न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि रैस्पों द्वारा अपनी खातेदारी की आराजीयात ख०न० 85 ग्राम महानन्दपुर पर आने जाने का कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने एवं हमेशा से अप्रार्थी/अपीलांट की आराजी ख०न० 345/81 से हमेशा से आते जाते रहने का कथन करते हुए अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र धारा 251 ए का पेश किया था। अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट/अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 251 ए का पेश किया गया तथा मौके की स्थिति हेतु तहसीलदार से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गंगपुर सिटी द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट पर अपीलांट/अप्रार्थीगण द्वारा ऐतराज किये जाने से नायब तहसीलदार से मौके की रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त रिपोर्ट अनुसार आराजी ख०न० 345/81 में 53 मीटर लम्बाई में एवं 8 मीटर चौड़ाई का रास्ता रैस्पों/प्रार्थीगण को डी एल सी दर की दो गुना राशि अपीलांट को दिये जाने की शर्त पर रास्ता प्रदान किया गया है। उभयपक्षकारान द्वारा इस न्यायालय में राजीनामा पेश कर उसमें अंकित किया कि पक्षकारों के मध्य राजीनामा इस प्रकार से हुआ है कि प्रथम पक्षकारान की खातेदारी की भूमि खसरा न० 5/81 स्थित ग्राम महानन्दपुर के रोड के पश्चिम दिशा की ओर से लगभग 139 फुट की दूरी में 25 फीट चौड़ा व 167 फीट लम्बा दोयम पक्ष को दिया जावेगा। यह रास्ता प्रथम पक्षकारान बाबन्द रहेगा। तथा हम प्रथम पक्षकारान की खातेदारी की भूमि में से रास्ते में गई भूमि के कुल क्षेत्रफल के एवज में आप दोयम पक्ष से रास्ते में गई भूमि के कुल क्षेत्रफल की डेढ़ गुना भूमि मुझ दोयम पक्ष द्वारा आप प्रथम पक्ष को दोनों खेतों के मध्य (खसरा न० 85 व ख०न० 345/81) की सीमा की ओर देने पर सहमति हुई है। मौके पर राजीनामा मुताबिक ख०न० 85 व ख०न० 345/81 की सीमा पर बाउन्ड्री तारफेंसिंग कर पक्की करवा लेगे। हम उभयपक्षकारान को इसमें आपत्ति नहीं है। मुताबिक राजीनामा प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष की खातेदारी की भूमि ख०न० 85 आपके ग्राम महानन्दपुर से कम की जाकर मुझ प्रथम पक्षकारान अपीलांट की खातेदारी की भूमि के अर्ज खाते में लगा दी जावे। यह सहमति हमारे समक्ष हुई है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में इस अमर का संशोधन करते हुए उक्त रास्ते की भूमि का उपयोग उपभोग करने का हम उभयपक्षकारान को अधिकार रहेगा। अन्य खेत वाला इस रास्ते से अपने खेत हेतु रास्ता मांगे जाने पर हम उभयपक्षकारान आपसी सहमति से निर्णय लेगे। इस प्रकार का राजीनामा उभयपक्षकारान द्वारा इस न्यायालय में पेश किया गया। अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/रैस्पों द्वारा अपीलांट की आराजीयात में से रास्ता चाहा गया है। अपीलांट भूमि के बदले डेढ़ गुना भूमि रैस्पों को दिये जाने पर सहमत है इसी प्रकार रैस्पों भी रास्ते के काम आने वाली भूमि के बदले भूमि दिये जाने पर सहमत है। दोनों पक्षों द्वारा आपसी सहमति दिये जाने तथा न्याय प्राप्ति के उद्देश्य से हम प्रकरण का निस्तारण सहमति के आधार पर किया जाना उचित समझते हैं। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि रैस्पों संख्या 1 द्वारा तहत न्यायालय ने रैस्पों/प्रार्थीगण के


राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

ऑर रों प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251 ए आर टी एक्ट स्वीकार कर यह आदेश दिया है कि रेस्पों की खातेदारी की भूमि खसरा न० 85 रकबा 0.88 है० वाके ग्राम महानन्दपुर में स्थित है , पर पहुँचन के लिए खसरा न० 345/81 में से 53 मीटर लम्बाई एवं 8 मीटर चौड़ाई कुल 424 वर्गमीटर गैर मुमकिन रास्ता कायम किये जाने के आदेश पारित किये है जिसके एवज में डी एल की दो गुना राशि प्रदान किये जाने के आदेश दिये गये है। अपीलांट को जमीन के बदले जमीन की आवश्यकता है क्योंकि जिस खसरा न० में होकर रास्ता प्रदान किया गया है उसका रकबा बहुत कम है । प्रस्तुत राजीनामा अनुसार अपीलांट डी एल सी स्वीकृत राशि ना लेकर खसरा न० 345/81 लेने एवं देने पर आपस में सहमत है। चूकि प्रकरण में अपीलांट माली समाज के है तथा रेस्पों न० 1 अनुसूचित जन जाति वर्ग का है। धारा 42 बी का वोइलेशन उक्त प्रकरण पर लागू नहीं होता है क्योंकि बेचान दान एवं हस्तान्तरण इत्यादि पर धारा 42 बी का वाईलेशन लागू होता है जबकि प्रकरण में स्वयं अनुसूचित जन जाति वर्ग का पक्षकार है, ने रास्ते के काम आने वाली जमीन के बदले जमीन अपीलांट को दिये जाने की सहमति स्वेच्छा से दी है। प्रकरण पर धारा 42 बी आर टी एक्ट के प्रावधान रास्ते की भूमि पर हमारी राय के मुताबिक चस्पा नहीं होते है। अपीलांट के नाम खसरा न० 345/81 रकबा 0.62 है० है। जिसका रकबा भी काफी कम है। किसी भी पक्ष को भूमि की हानि नहीं होनी चाहिए। रास्ते का प्रयोजन सार्वजनिक है। लिहाजा न्यायहित में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील उभयपक्षकारान की सहमति/राजीनामे के आधार पर अंशिक स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः अपीलं अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर मलारना डूंगर के मुकदमा न० 11/19 में पारित निर्णय दिनांक 3.10.19 आंशिक रूप से इस आशय की हद तक निरस्त किया जाता है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में रास्ते के काम आने वाली भूमि की एवज में डी एल सी दर से दो गुना कुल राशि 128006/- अपीलांट को दिये जाने के आदेश की हद तक निरस्त किया जाकर रेस्पों को आदेश दिये जाते है कि खसरा न० 345/81 में 25 गुणा 167 फीट अर्थात 388 वर्गमीटर की डेढ गुना भूमि अर्थात 582 वर्गमीटर भूमि रेस्पों न० 1 , अपीलांट को (आराजी ख० न० 85 व 345/81) की सीमा पर देवे था उक्त दी गई भूमि की नक्शा ट्रेस में रेस्पों संख्या 2 इसी अमर की तरमीम दुरुस्ती की जाकर अपीलांट के खाते राजस्व रिकार्ड में 582 वर्गमीटर भूमि दर्ज की जावे।

निर्णय आज दिनांक 02.4.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।


(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर